

3. स्टेशन पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। प्लेटफार्म नं० 1 पर एक जलशीतक की भी व्यवस्था की गई है।

4. प्लेटफार्म नं० 1 पर 529.66 वर्ग मीटर और प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर 172.43 वर्गमीटर क्षेत्र पर सायबान की व्यवस्था की गई है।

5. वर्तमान यातायात के स्तर के लिए ये व्यवस्थायें पर्याप्त समझी गई हैं।

वातानुकूलित शयनयानों के स्थान पर डी-लक्स वातानुकूलित यान

2839. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वातानुकूलित-शयन यानों के स्थान पर बैठने के स्थान वाले डी-लक्स वातानुकूलित यानों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) प्रथम चरण में ऐसे कितने यानों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने यात्रियों को सुविधा मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बरेली और मुरादाबाद के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाना

2840. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे के बरेली एवं मुरादाबाद रेल स्टेशनों के बीच बहुत वर्षों से इकहरी रेल लाइन है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे दोहरी करने का है, यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उसका निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा, और कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान इकहरी लाइन ही पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Preferential Treatment to Railwaymen's wards in regard to Employment

2841 SHRI VASANT SATHE:
SHRI K. RAMAMURTHY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Ministry is considering a proposal to accord a preferential treatment to railwaymen's wards in employment;

(b) if so, details of the proposal under consideration;

(c) the decision taken in the matter; and

(d) whether views of the Law/Home Ministry have been sought/obtained and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) (a) to (d). A proposal has been under consideration for giving some preference to wards/sons/children of retired employees on compassionate grounds taking into account the indigent circumstances of the family. It is under examination in consultation with the Law Ministry.